न्यायमूर्ति बी.एस. ढिल्लों के समक्ष

एम.के. मक्कड़ - याचिकाकर्ता

बनाम

उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त और अन्य - प्रतिवादी

1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1921

6 अगस्त 1979

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम (1914 का 1) - धारा 58 (2) (ई) और 59 (डी) और (एफ) - पंजाब शराब लाइसेंस नियम 1956 - नियम 4 प्रावधान - एल 2 लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को ऐसा दूसरा लाइसेंस रखने से रोक दिया गया राज्य में लाइसेंस-ऐसा नियम बनाने की शक्ति-क्या राज्य सरकार में निहित है-वित्तीय आयुक्त नियम 4 में परंतुक जोड़कर ऐसी रोक लगाता है-नियम 4 में परंतुक-क्या अधिकारातीत है।

माना गया कि पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम 1914 की धारा 58 (2) के खंड (ई) के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि राज्य सरकार को अवधियों और इलाकों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। जो, और वे व्यक्ति, या व्यक्तियों के वर्ग, जिन्हें, किसी भी नशीले पदार्थ की थोक या खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए जा सकते हैं और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित किया जा सकता है जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं। . किस वर्ग के व्यक्ति या किस वर्ग के व्यक्तियों को लाइसेंस लेने से रोका गया है और वे लाइसेंस लेने के लिए योग्य हैं, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। अधिनियम की धारा 59 (ए) के प्रावधान वित्तीय आयुक्त को किसी भी नशीले पदार्थ के निर्माण, आपूर्ति, भंडारण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। इस धारा के खंड (डी) के संबंध में ईएसआई वित्तीय आयुक्त को फीस के निर्धारित पैमाने या किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास में देय फीस तय करने के तरीके या कैंट के भंडारण के संबंध में शक्ति देता है। यह शक्ति शायद ही किसी व्यक्ति या वर्ग को छूती है और उसे लाइसेंस लेने से रोक दिया जाता है। जहां तक खंड (एफ) का संबंध है, यह किसी भी लाइसेंस, परमिट या प्रदान किए जाने वाले प्राधिकार, उसके अधीन और शर्तों को निर्धारित करने से संबंधित है। लाइसेंस देने से इंकार करने को लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। पंजाब राज्य में कहीं भी एल. 2 में लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को लाइसेंस रखने से वंचित करने वाला नियम बनाना, लाइसेंस की शर्त नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, वित्तीय आयोग द्वारा प्रख्यापित

नियम 4 अधिकारातीत है क्योंकि उसके पास ऐसे नियम बनाने की धारा 59 के तहत कोई शक्ति नहीं है।

(पैरा 4 और 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका प्रार्थना करती है कि:-

(i) कृपया मामले के रिकार्ड तलब किये जायें;

(ii) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादियों और/या उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ परमादेश, सर्टिओरारी और/या किसी अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करने में प्रसन्न होगा। कलेक्टर (अनुबंध पी. 3) और आयुक्त (अनुबंध पी. 6) के क्रमश: 31 मार्च, 1979 और 16 मई, 1979 के आक्षेपित आदेशों को रद्द करें और उन्हें लागू करने से रोकें;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (4) के तहत अपेक्षित प्रस्ताव की सूचना को समाप्त कर दिया जाए; रिट-याचिका की लागत भी प्रदान की जाए। आगे प्रार्थना की गई है कि इस रिट-याचिका का निपटारा होने तक निम्नलिखित राहतें प्रदान की जाएं:-

(ए) कलेक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश दिनांक 31 मार्च, 1979 (अनुलग्नक पी. 3) और आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 1) के 16 मई, 1979 (अनुलग्नक पी. 6) के संचालन पर रोक लगाई जाए;

(बी) याचिकाकर्ता को पहले की तरह अपना लाइसेंस संचालित करने की अनुमति दी जाए;

(सी) इस याचिका के विभिन्न अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है। इस तरह के अन्य आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया भी दिए जा सकते हैं।

आगे प्रार्थना की गई है कि चूंकि यह माननीय न्यायालय अवकाश पर है, इसलिए विवादित आदेशों (अनुलग्नक पी. 3 और पी. 6) के संचालन पर अंतरिम रोक लगाई जाए।

तीरथ सिंह मुंजराल, अधिवक्ता।

डी.एन.रामपाल, वकील, ए.जी. (पंजाब) के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति बी.एस. ढिल्लों, (मौखिक):

(1) याचिकाकर्ता पिछले कई वर्षों से पंजाब राज्य में विदेशी शराब का कारोबार कर रहा है। उसके पास मुकेरियां और तलवाड़ा के लिए पंजाब शराब लाइसेंस नियमों के तहत एल-2 वर्णित लाइसेंस था | याचिकाकर्ता ने 3 नवंबर, 1978 को निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 1979-80 के लिए दोनों लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। प्रतिवादी नंबर 2, कलेक्टर-सह-उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, जालंधर डिवीजन, जालंधर, वह प्राधिकारी है जिसके पास इस तरह के लाइसेंस को नवीनीकृत करने की शक्ति है। उक्त प्रतिवादी ने, अपने आदेश दिनांक 29 मार्च, 1979 द्वारा, याचिकाकर्ता के दोनों लाइसेंसों को नवीनीकृत किया और इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को प्रत्येक विक्रेता के लिए एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के रूप में 5,000 रुपये की राशि जमा करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। रुपये की बैंक गारंटी वर्ष 1979-80 के लिए 10,000. याचिकाकर्ता ने रुपये की राशि जमा की। 31 मार्च, 1979 को तलवाड़ा में दुकान की कीमत 5,000 रु. हालाँकि, 30 मार्च, 1979 की एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा, उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त ने, वित्तीय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 के नियम 4 में निम्नलिखित शर्तों में प्रावधान जोड़ा: - "बशर्ते कि जिस व्यक्ति को पंजाब राज्य में कहीं भी फॉर्म एल-2 में लाइसेंस दिया गया है, उसे फॉर्म एल-2 में दूसरा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।"

(2) इस प्रावधान के मद्देनजर, कलेक्टर-सह-उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त ने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के अपने आदेश की समीक्षा की और 31 मार्च, 1979 को आदेश जारी किया, जिसकी प्रति रिट याचिका के साथ संलग्नक 'पी-3' है। पंजाब शराब लाइसेंस नियमों में संशोधन के मद्देनजर, तलवाड़ा में याचिकाकर्ता के वर्ष 1979-80 के लिए एल-2 लाइसेंस का नवीनीकरण वापस ले लिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 का यह आदेश इस याचिका में हमले का विषय है | याचिकाकर्ता ने उत्पाद शुल्क और आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जिसे कराधान आयुक्त के आदेश दिनांक 16 मई, 1979 के तहत उनके द्वारा खारिज कर दिया गया। इस रिट याचिका में अपील के तहत आदेश को भी चुनौती देने की मांग की गई है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मुंजराल ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, वित्तीय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते समय, उस नियम को लागू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके द्वारा उन्होंने शक्तियों के रूप में नियम 4 में प्रावधान जोड़ा है किस वर्ग के व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार हैं, इसके लिए नियम बनाने का अधिकार पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 58 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के पास है। विद्वान वकील का तर्क है कि रिटर्न में दलील दी गई है कि उक्त नियम वित्तीय आयुक्त द्वारा उनमें निहित शक्तियों के मद्देनजर बनाया जा सकता है।

धारा 59 के तहत, खंड (डी) और (एफ), जांच में टिक नहीं सकते। इस विवाद की जांच करने की दृष्टि से, अधिनियम की धारा 58 के खंड (ई) के प्रावधान, और अधिनियम की धारा 59 के खंड (डी) और (एफ) को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"58. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ:

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार नियम बना सकती है, -

****

(ई) उन अवधियों और इलाकों को विनियमित करना जिनके लिए, और व्यक्तियों, या व्यक्तियों के वर्गों को, जिन्हें किसी भी मादक पदार्थ की थोक या खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए जा सकते हैं और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करना जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रदान किया जा सकता है।

****

"59. वित्तीय आयुक्त की नियम बनाने की शक्तियाँ:- वित्तीय आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकते हैं-

****

डी) किसी लाइसेंस, परमिट, या पास के संबंध में या किसी नशीले पदार्थ के भंडारण के संबंध में फीस का पैमाना या देय फीस तय करने का तरीका निर्धारित करना।

****

(एफ) निम्नलिखित मामलों के प्रावधान सहित किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास को दिए जाने वाले प्राधिकार, प्रतिबंधों और शर्तों को निर्धारित करना: -

(i) किसी भी नशीले पदार्थ के साथ हानिकारक या आपत्तिजनक समझे जाने वाले किसी भी पदार्थ के मिश्रण पर प्रतिबंध;

(ii) किसी लाइसेंस प्राप्त निर्माता या लाइसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा शराब की मात्रा को उच्च से निम्न शक्ति में कम करने का विनियमन या निषेध;

(i) उस ताकत या कीमत का निर्धारण, जिसके नीचे कोई भी नशीला पदार्थ बेचा, आपूर्ति या कब्ज़ा नहीं किया जाएगा; (iv) नकदी को छोड़कर किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध; (v) उन दिनों और घंटों का निर्धारण, जिनके दौरान किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को खुला रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, और विशेष अवसरों पर ऐसे परिसरों को बंद किया जा सकता है; (vi) उस परिसर की प्रकृति का विवरण जिसमें कोई नशीला पदार्थ बेचा जा सकता है; और ऐसे परिसरों पर प्रदर्शित किया जाने वाला नोटिस; (vii) बनाए रखे जाने वाले खातों का प्रपत्र और लाइसेंस धारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न; और (viii) लाइसेंस के हस्तांतरण पर प्रतिबंध या विनियमन। (4) अधिनियम की धारा 58(2) के खंड (ई) के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि राज्य सरकार को उन अवधियों और स्थानों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं, जिनके लिए और व्यक्ति , या व्यक्तियों के वर्ग, जिन्हें किसी भी नशीले पदार्थ की थोक या खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए जा सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या को विनियमित किया जा सकता है।

(4) अधिनियम की धारा 58 (2) के खंड (ई) के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि राज्य सरकार को उन अवधियों और स्थानीयताओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं, जिनके लिए और व्यक्ति , या व्यक्तियों के वर्ग, जिन्हें किसी भी नशीले पदार्थ की थोक या खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए जा सकते हैं और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित किया जा सकता है जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं। किस वर्ग के व्यक्तियों या वर्गों के व्यक्तियों को लाइसेंस लेने से रोका गया है या वे लाइसेंस लेने के लिए योग्य हैं, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अधिनियम की धारा 59 (ए) के प्रावधान वित्तीय आयुक्त को किसी भी नशीले पदार्थ के निर्माण, आपूर्ति, भंडारण या बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करते हैं। इस धारा के खंड (डी) के संबंध में, उक्त प्रावधान वित्तीय आयुक्त को किसी भी लाइसेंस, परमिट, या पास के संबंध में या भंडारण के संबंध में फीस के पैमाने या देय शुल्क तय करने के तरीके को निर्धारित करने की शक्ति देते हैं। कोई भी नशीला पदार्थ. यह शक्ति शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूती है जो लाइसेंस लेने से वंचित हैं। जहां तक इस धारा के खंड (एफ) का संबंध है। यह किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास के अधिकार, उसके तहत प्रतिबंधों और शर्तों को निर्धारित करने से संबंधित है। बिना सोचे-समझे लाइसेंस देने से इनकार को लाइसेंस की शर्त कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए,

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा मुकेरियां में रखे गए लाइसेंस को नवीनीकृत कर दिया गया था और माना जाता है कि उस लाइसेंस की शर्तों में कोई शर्त नहीं जोड़ी गई है, जबकि तलवाड़ा के संबंध में उसके पास जो लाइसेंस था, उसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। पंजाब राज्य में कहीं भी एल-2 में एक लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को अन्य एल-2 लाइसेंस रखने से रोकने के लिए नियम बनाना, लाइसेंस की शर्त नहीं कहा जा सकता है। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रामपाल ने नियम बनाने के लिए शक्ति के स्रोत को उचित ठहराने के लिए अधिनियम की धारा 59 में किसी अन्य प्रावधान पर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया है, जिस पर हमला हो रहा है।

(5) इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्तीय आयुक्त ने पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 के नियम 14 को तैयार किया है, जो व्यक्तियों के एक वर्ग को एक विशेष प्रकार का लाइसेंस देने से रोकता है यदि उनके पास किसी अन्य प्रकार का लाइसेंस है। , लेकिन मेरे समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि उक्त नियम की वैधता को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई। इसलिए, नियम 14 की उपस्थिति का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं होगा कि वित्तीय आयुक्त के पास ऐसे नियम बनाने की शक्ति है। यह बताया जा सकता है कि पुर जाब नशीले पदार्थ लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 के खंड 7-ए के प्रावधान हैं। निम्नलिखित शब्दों में:-

“7-ए. केवल जनता के लिए विदेशी शराब की थोक और खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म एल-2 में लाइसेंस किसी व्यक्ति, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित निकाय या अविभाजित परिवार को नहीं दिया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसी फर्म का कोई भागीदार या ऐसी सोसायटी का कोई सदस्य या कोई शेयरधारक ऐसा निकाय या ऐसे परिवार का कोई भी सदस्य, जैसा भी मामला हो, फॉर्म एल-13, एल-14, एल में देशी शराब का लाइसेंस रखता है या रखता है। -14-ए या एल-14-बी उस वर्ष से पहले के पिछले तीन वर्षों के दौरान जिसमें फॉर्म एल-2 में लाइसेंस के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है या जो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ हित में जुड़ा हुआ है। या उस वर्ष से पहले पिछले तीन वर्षों के दौरान फॉर्म एल-13, एल-1- एल-14-ए या एल-14-बी में देशी शराब का लाइसेंस रखा हो, जिसमें फॉर्म एल-2 में लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया हो। प्रस्तुत किया गया है।"

यह नियम किसी व्यक्ति को उसमें उल्लिखित दो प्रकार के एलआईसी रखने से भी रोकता है। यह नियम राज्य सरकार द्वारा धारा 58 (2) (ई) ओ अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के तहत बनाया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, मेरी स्पष्ट राय है कि नियम 4 का प्रावधान, जिसे फ़िना आयुक्त द्वारा प्रख्यापित किया गया है, अधिकारातीत है, और वित्तीय आयुक्त को इस तरह का नियम बनाने के लिए अधिनियम की धारा 59 के तहत कोई शक्ति नहीं है। सी तदनुसार, नियमों के नियम 11-ए का प्रावधान भी रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह एक प्रक्रियात्मक नियम है। चूँकि एफ के नियम 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया है, इसलिए आक्षेपित

आदेश को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि पहले प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं लाइसेंस के नवीनीकरण का आदेश दिया था और यह स्पष्ट रूप से किया गया था याचिकाकर्ता ने कानून की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया था।

(6) ऊपर दर्ज कारणों से, इस रिट याचिका में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह औपचारिकताओं को पूरा करे, यदि पहले से नहीं किया गया है, जैसा कि प्रशासन चाहता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा